Daily Current Affairs

Date : 02 June, 2026

UTKARSH CLASSES — CIVIL SERVICES

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'पैमाना' रिपोर्ट में राजस्थान
2.	आत्मघाती ड्रोन 'दिव्यास्त्र Mk-1' का सफल परीक्षण
3.	'PM सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' में राजस्थान
4.	राजस्थान में पहली बार दर्ज हुआ 'सिस्तान सैंड बोआ' (Eryx sistanensis)
5.	सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIPS)
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जाँच पहल का शुभारंभ 2. स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप – 2026 3. 75वीं सीनियर स्टेट एक्वेटिक चैंपियनशिप – 2026
7.	अर्हत सारिपुत्र और अर्हत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष
8.	उदंत मार्तण्ड
9.	पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) के 6 वर्ष पूरे हुए
10.	प्रगति अभ्यास
11.	AUKUS
12.	शांगरी-ला डायलॉग
13.	भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)
14.	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन
15.	बन्नी घास के मैदान

राजस्थान परिदृश्य

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'पैमाना' रिपोर्ट में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 'पैमाना' (PAIMANA) पोर्टल की नवीनतम फ्लैश रिपोर्ट में राजस्थान में संचालित बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी आँकड़े जारी किए गए।

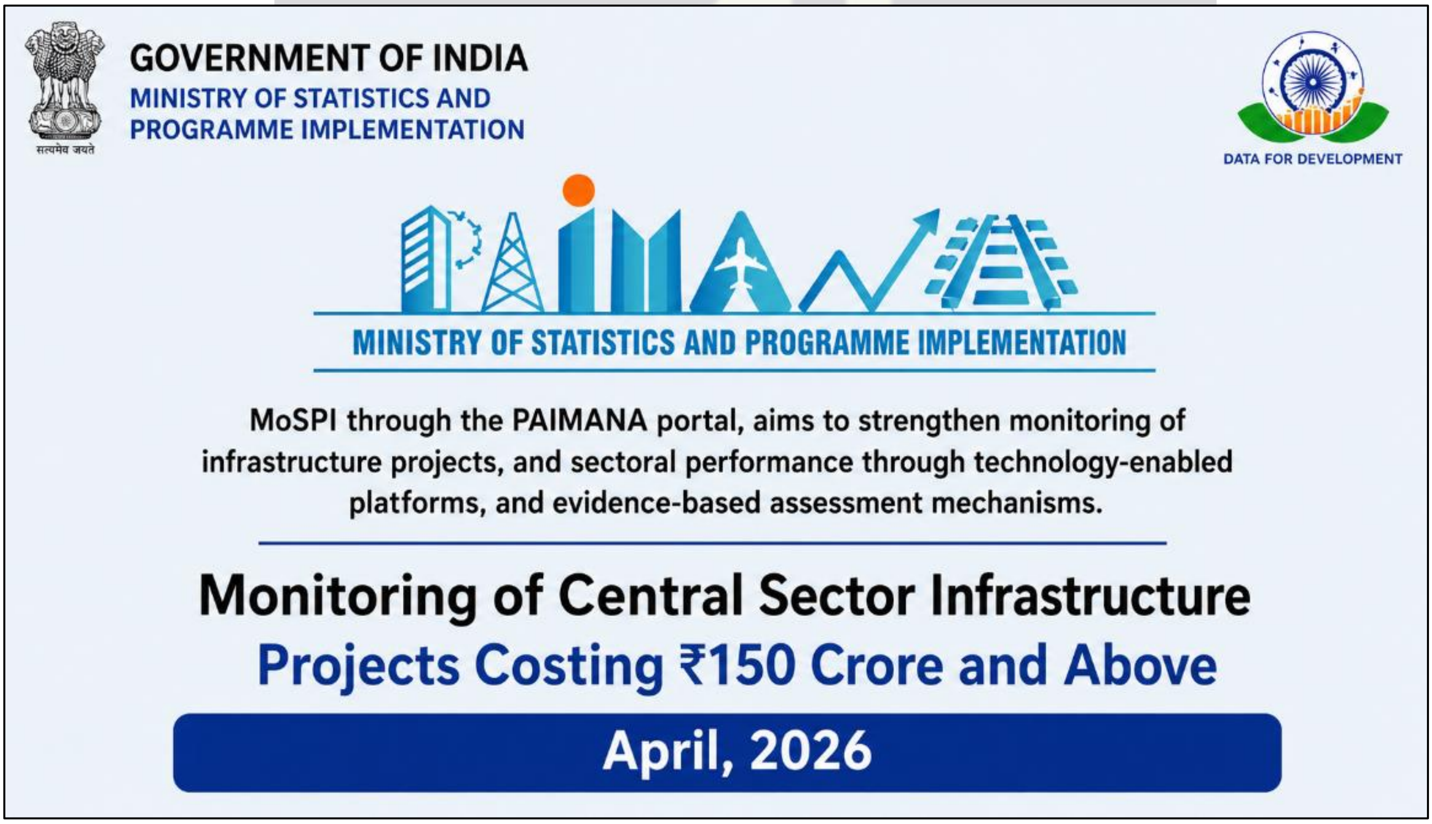

मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेट्रोलियम और नागरिक उड्डयन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की लगभग ₹2.72 लाख करोड़ से अधिक की कुल 81 परियोजनाएँ प्रगतिरत हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

मुख्य प्रोजेक्ट:

HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL)

- **लागत :** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत संचालित इस परियोजना की कुल लागत ₹79,459 करोड़ है।
- HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) को 18 सितंबर, 2013 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमश: 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ शुरू किया गया।
- **परियोजना को स्वीकृति :** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 09 अक्टूबर, 2017 को।
- यह BS-6 मानक वाली देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफायनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है।
- इस रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है, जिसमें 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं।
- राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में आयातित कच्चे तेल (7.5 MMTPA) के साथ-साथ राजस्थान में उत्पादित क्रूड ऑयल (1.5 MMTPA) को भी संसाधित (Processed) किया जा सकेगा।

रेलवे अवसंरचना :

- राजस्थान में उत्तर-पश्चिम रेलवे की 23 परियोजनाएँ संचालित हैं, जिनकी लागत ₹1,64,998 करोड़ है।
- **वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर :** भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से लगभग 564 किलोमीटर का खंड राजस्थान से होकर गुजरता है। गुजरात-हरियाणा-महाराष्ट्र-राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले इस फ्रेट कॉरिडोर का कार्य पूर्ण होने वाला है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **विस्तार :** जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT), मुंबई से दादरी (उत्तर प्रदेश) तक।
- **लगता :** ₹1,24000 करोड़।
- **धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले रेलवे के प्रोजेक्ट्स :** राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट्स में देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा, नाथद्वारा-नाथद्वारा टाउन, पुष्कर-मेड़ता सिटी और पोकरण-रामदेवरा नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है।

एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर :

- राज्य में ₹75,000 करोड़ से अधिक की एनर्जी ट्रांसमिशन की 19 परियोजनाएँ संचालित है, जिनमें बहुराज्यीय प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।
- ₹25,000 करोड़ की लागत वाली 'राजस्थान पार्ट-1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना' राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है।
- **नोट :** पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर) के सोलर और विंड ज़ोन से बिजली निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष पारेषण अवसंरचना विकसित की गई है।

विमानन अवसंरचना :

- राजस्थान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा वर्तमान में ₹2,874 करोड़ की लागत से 3 महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है।
  - कोटा-बूँदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा।
  - जोधपुर घरेलू यात्री टर्मिनल।
  - उदयपुर एकीकृत टर्मिनल परियोजना।

सड़क निर्माण :

- राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा लगभग ₹18,000 की लागत से 28 सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाएँ संचालित है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

पैमाना रिपोर्ट के बारे में :

- **जारीकर्ता :** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- **पूरा नाम :** प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग (PAIMANA)
- 'पैमाना' (PAIMANA) एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल है, जो ₹150 करोड़ व उससे अधिक की लागत वाली प्रमुख केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करता है।
- **उद्देश्य :** अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण, विलंब (delays), और लागत वृद्धि की प्रभावी निगरानी करना तथा डेटा-संचालित निर्णय लेना।

UTKARSH CIVIL SERVICES

आत्मघाती ड्रोन 'दिव्यास्त्र Mk-1' का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन (आत्मघाती ड्रोन) 'दिव्यास्त्र Mk-1' का सफलतापूर्वक परिचालन प्रदर्शन और परीक्षण किया।

मुख्य बिन्दु:

- **विकास :** स्वदेशी स्टार्टअप 'होवरिट' (Hoverit) द्वारा।
- **मारक क्षमता (रेंज) :** यह ड्रोन 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है।
- **फ्लाइट टाइम :** लगातार 5 घंटे तक हवा में रहकर निगरानी करने में सक्षम।
- **मल्टी-मिशन उपयोग :** इसे खुफिया जानकारी जुटाने, सर्विलांस (निगरानी), टोही मिशन (ISR) और सटीक पिन-पॉइंट हमलों के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह ड्रोन AI-पावर्ड है और रीयल-टाइम इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड (EO/IR) सेंसर तथा संचार रिले प्रणालियों से लैस है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **मिशन दिव्यास्त्र :** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का ऐतिहासिक उड़ान परीक्षण था।
- इसके तहत पहली बार MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) तकनीक का सफल परीक्षण किया गया, जिससे भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया।

UTKARSH CIVIL SERVICES

‘PM सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’ में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- ‘PM सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’ के अन्तर्गत मई, 2026 में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए।

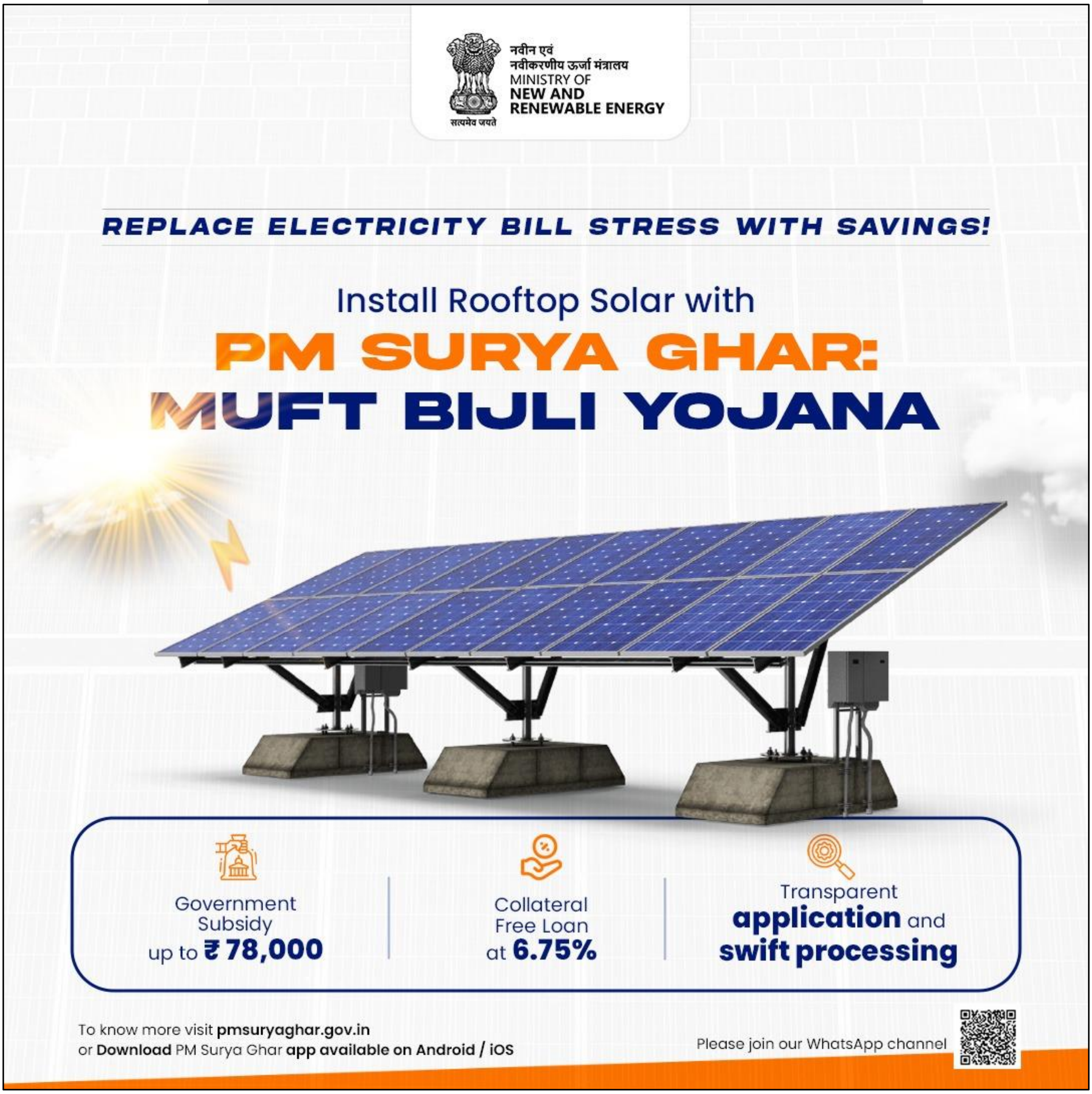

मुख्य बिन्दु:

- **नोट :** फरवरी, 2024 में योजना शुरू होने के बाद यह राजस्थान में किसी भी एक माह का अब तक का सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है।
- मई, 2026 में कुल इंस्टॉलेशन में जोधपुर डिस्कॉम में 9,316, जयपुर डिस्कॉम में 9,204 तथा अजमेर डिस्कॉम में 8,112 उपभोक्ताओं ने अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाए।
- उल्लेखनीय है कि 'PM सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना' के अंतर्गत प्रदेश में 830 मेगावाट (MW) क्षमता के लगभग 2.17 लाख रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।

- **लॉन्च :** 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
- **संबंधित मंत्रालय :** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- **उद्देश्य :** रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना की सुविधा के द्वारा घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- **लक्ष्य :** मार्च, 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना।
- राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024' जारी की है, जिसमें रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग के साथ-साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग के प्रावधान किए गए हैं।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी:

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट)	उपयुक्त रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता	सब्सिडी सहायता
0-150	1-2 kW	₹ 30,000/- से ₹ 60,000/-
150-300	2-3 kW	₹ 60,000/- से ₹ 78,000/-
> 300	3 kW से ऊपर	₹ 78,000/-

राजस्थान में पहली बार दर्ज हुआ 'सिस्तान सैंड बोआ' (Eryx sistanensis)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, थार मरुस्थल में पहली बार साँप की प्रजाति सिस्तान सैंड बोआ (Eryx sistanensis) को पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया।

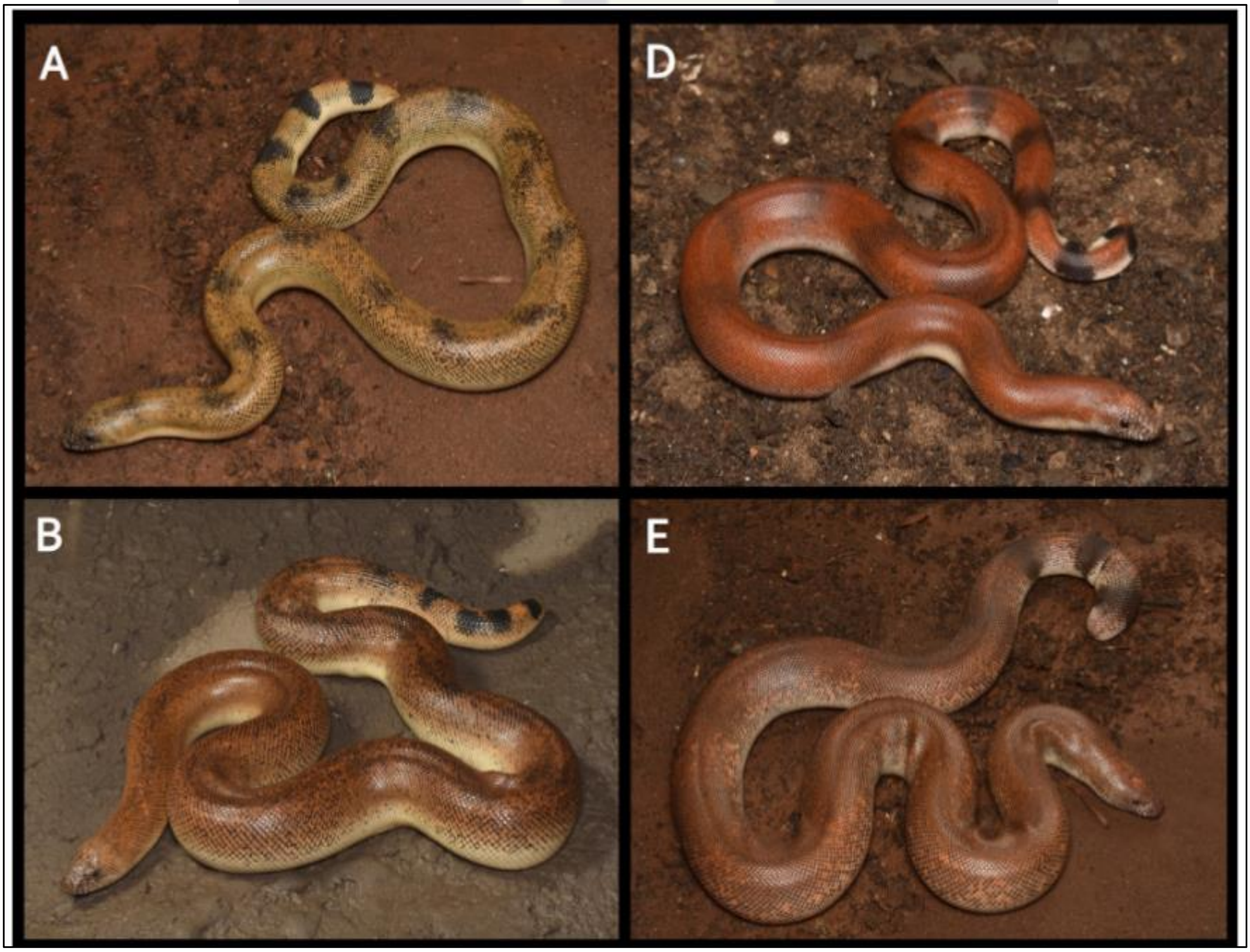

मुख्य बिन्दु:

- यह खोज जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा (Journal of Threatened Taxa) में प्रकाशित हुई।

- यह प्रजाति चूरू, सीकर और बीकानेर के जोड़बीड कंजर्वेशन रिजर्व में दर्ज की गई है।
- इस नई खोज के साथ ही भारत में पाई जाने वाली बोआ (Boa) साँप की प्रजातियों की संख्या 4 हो गई।
- 'सिस्तान सैंड बोआ' बिना जहर वाला (गैर-विषैला) साँप है।
- **भौगोलिक उपस्थिति :** यह प्रजाति मुख्य रूप से ईरान और पाकिस्तान के शुष्क इलाकों में पाई जाती है।
- **नामकरण :** इस साँप को पहली बार वर्ष 2020 में ईरानी वैज्ञानिकों द्वारा एक नई प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और इसका नाम ईरान के 'सिस्तान' प्रांत के नाम पर रखा गया था।

UTKARSH CIVIL SERVICES

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIPS)

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में संचालित 'सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIPS)' की समीक्षा बैठक हाल ही में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित की गई।

मुख्य बिन्दु:

- **योजना के बारे में :** राज्य में वंचित वर्ग; यथा - बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिखारी/निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्तियों, HIV से ग्रसित व्यक्तियों एवं वृद्धजनों के कल्याण तथा अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में सरकार (केंद्र और राज्य) से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिये 'सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021' का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत अधिसूचित वंचित वर्ग :

- **महिला :** किसी विधि के अन्तर्गत कोई हिंसा, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, मानसिक बीमार, संकटग्रस्त अवस्था में मौजूद महिला अथवा एकल महिला।
- **बालक / बालिका :** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) में परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक।
- संबंधित विभाग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।

संस्था के लिए पात्रता :

- अलाभकारी संस्था की स्थापना में न्यूनतम ₹50 लाख का पूँजीगत निवेश अथवा न्यूनतम 25 लाभार्थियों हेतु संचालन आवश्यक है।
- वंचित वर्ग की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार के कार्य हेतु राज्य में कार्यरत अलाभकारी संस्था का न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व से संबंधित सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- **सुविधाएँ /रियायत :** राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी संस्था को निम्नानुसार एक अथवा एक से अधिक सुविधाएँ/रियायत/छूट प्रदान की जाती है।

  (i) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।

  (ii) आवंटित भूमि पर लीज में 100 प्रतिशत छूट।

  (iii) नियमन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।

  (iv) भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।

  (v) स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट।

  (vi) प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट।
- **नोट :** ऐसी अलाभकारी संस्थाएँ जिनमें न्यूनतम ₹5 करोड़ का पूँजीगत निवेश हो अथवा 100 लाभार्थियों हेतु कार्यशील हो, को उपरोक्त वर्णित सुविधाएँ/रियायत/छूट के अतिरिक्त कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में अतिरिक्त सुविधाएँ/रियायत/छूट प्रदान की जाती है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

✂️ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	**श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जाँच पहल का शुभारंभ** ■ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच पहल की शुरुआत की गई है। ■ **पात्रता :** 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी श्रमिक (जो ESIC ढाँचे के अंतर्गत आते हैं) ■ **राज्य स्तरीय शुभारंभ :** 07 मई, 2026 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर द्वारा।
2.	**स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप - 2026** ■ **आयोजन :** 30 और 31 मई, 2026 ■ **आयोजन स्थल :** सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। ■ **आयोजक :** राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन। ■ चैंपियनशिप में झुंझुनूं के आदेश गरसा और जयपुर की डोना धाकड़ ने क्रमशः पुरुष एवं महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ का खिताब जीता।
3.	**75वीं सीनियर स्टेट एक्वेटिक चैंपियनशिप – 2026** ■ **आयोजन :** जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में। ■ चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की योग्या सिंह और टोंक की दक्षिणा जोशी ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। ■ योग्या सिंह ने महिला 100 मीटर बैकस्ट्रोक में 1:08.46 मिनट का समय निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि दक्षिणा जोशी ने महिला 200 मीटर बटरफ्लाई में 2:22.03 मिनट का समय दर्ज किया।

इतिहास एवं संस्कृति

अर्हत सारिपुत्र और अर्हत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष

(स्रोत: PIB)

चर्चा में क्यों?

- भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों; अर्हत सारिपुत्र और अर्हत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया के गंदंतेगचिनलेन मठ में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। ये अवशेष सदियों तक सांची के पवित्र स्तूपों में संरक्षित थे।

मुख्य बिन्दु:

अर्हत सारिपुत्र

- इन्हें भगवान बुद्ध का मुख्य शिष्य (अग्गसावक) और दो 'धम्म-सेनापतियों' में से एक माना जाता है।
- वह पहले ऐसे मानव शिष्य थे, जिन्होंने सीधे बुद्ध से 'अभिधम्म' का पाठ सीखा था। उन्हें अभिधम्म परंपरा को आगे बढ़ाने वाला पहला शिक्षक माना जाता है।

अर्हत मौद्गल्यायन

- मौद्गल्यायन भगवान बुद्ध के दूसरे मुख्य शिष्य थे।
- उनका एक अन्य नाम 'कोलिता' भी था।
- उन्होंने बुद्ध के पुत्र राहुल के शिक्षक के रूप में कार्य किया था।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

उदंत मार्तण्ड

(स्रोत: DD NEWS)

मुख्य बिन्दु:

- **विश्व के प्रथम हिंदी समाचार-पत्र 'उदंत मार्तण्ड' के प्रथम प्रकाशन की तिथि के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।**
- **इसका प्रकाशन 1826 ई. में कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में किया गया था।**
- **16 फरवरी, 1826 को शुक्ल ने कलकत्ता की बांसतला गली के मन्नू ठाकुर के सहयोग से हिंदी समाचार-पत्र शुरू करने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त की।**
- **यह भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का प्रतीक है।**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

योजनाएँ एवं नीतियाँ

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) के 6 वर्ष पूरे हुए

(स्रोत: PIB)

चर्चा में क्यों?

- जून 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल रेहड़ी-पटरी लगाने वाले वेंडर्स को औपचारिक संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को सुरक्षित करने में सहायता करती है।

मुख्य बिन्दु:

योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **ऋण सहायता:** लगभग 1 करोड़ आवेदकों को ऋण की सुविधा प्रदान की गई और बिना किसी गारंटी (कोलेटरल फ्री) के 17,800 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि वितरित की गई।

- **बड़ी संख्या में लाभार्थी:** औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़कर 75.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाया गया।
- इस योजना के कारण लाभार्थियों की औसत आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **महिला सशक्तीकरण:** लक्षित वित्तीय सहायता के माध्यम से 34.81 लाख महिला स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ मिला है।
- **डिजिटल समावेशन:** 55 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल तकनीकों से जोड़ा गया, जिससे कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिला है।
- **पुरस्कार:** इस योजना को नवाचार श्रेणी (केंद्र स्तर) में 'प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार (2023)' से सम्मानित किया गया।

पीएम स्वनिधि

- **मंत्रालय:** केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **योजना-अवधि:** जून 2020 से 2030 तक।
- इसे 2025 में पुनर्गठित किया गया और ऋण देने की अवधि को 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 तक कर दिया गया।
- **कार्यान्वयन:** केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संयुक्त रूप से।
- **उद्देश्य:** रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं को पहचान प्रदान करने, बिना कुछ गिरवी रखे कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने जैसे उपायों से उनकी चिंताओं को दूर करना और चुनौतियों का समाधान करना।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

प्रगति अभ्यास

(स्रोत: PIB)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के साझेदारों के लिए पहला बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति/PRAGATI 2026 संपन्न किया।

मुख्य बिन्दु:

- प्रगति से आशय है: 'पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन।'

प्रगति अभ्यास

- **अवधि:** दो सप्ताह
- **प्रतिभागी देश:** भारत, साथ में क्षेत्र के 12 मित्र भागीदार देश- भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम।
- **उद्देश्य:** प्रतिभागी सेनाओं के बीच आतंकवाद-रोधी क्षमता वृद्धि, विशिष्ट सामरिक कौशल विकास, बहुराष्ट्रीय संचालनीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ावा देना।

UTKARSH CIVIL SERVICES

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

AUKUS

(स्रोत: ECONOMIC TIMES)

चर्चा में क्यों?

- AUKUS के सदस्य देशों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। इनमें अत्याधुनिक अंडरवाटर ड्रोन का विकास करना एवं 2027 से ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती करना शामिल हैं।

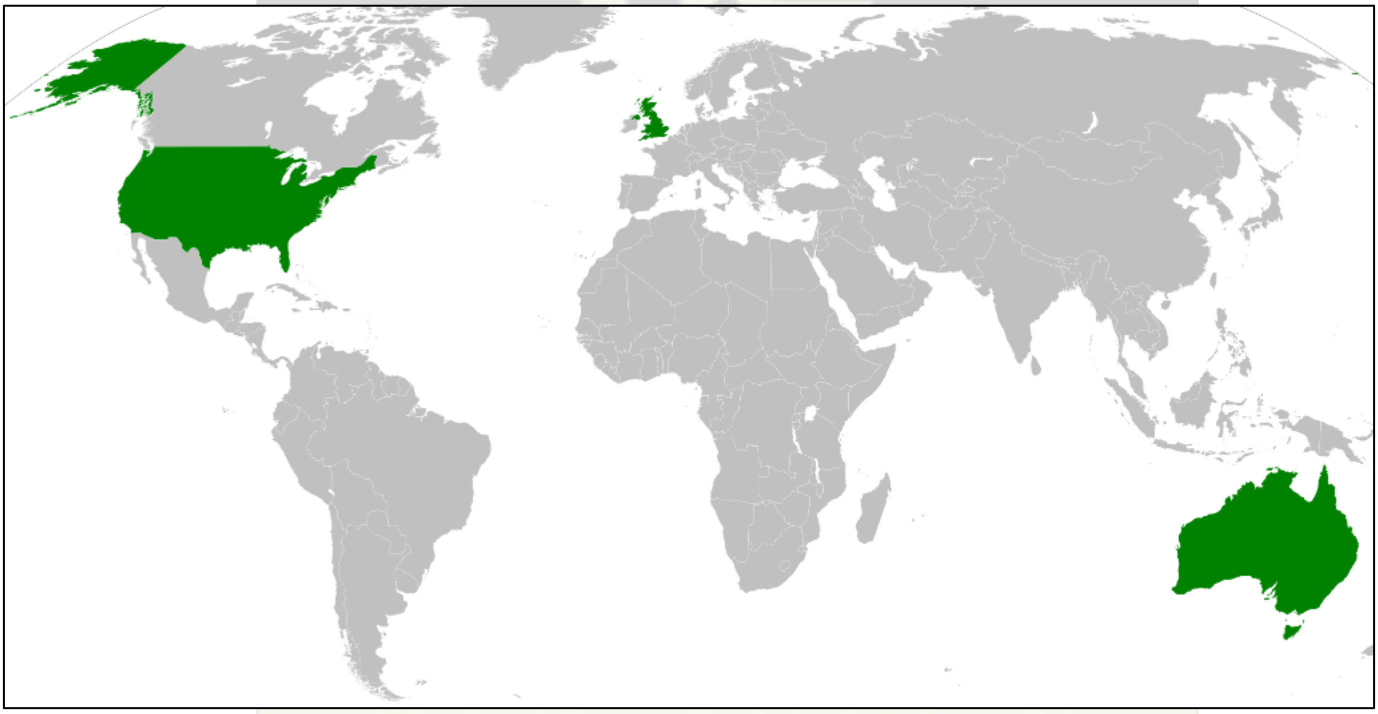

मुख्य बिन्दु:

AUKUS

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 2021 में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक रक्षा गठबंधन के रूप में हुई थी।
- **उद्देश्य:** रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी क्षमता के एकीकरण को तेज़ करना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास के तहत तीनों देशों की औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- **इसके दो प्रमुख स्तंभ हैं:**
  - **स्तंभ 1:** यह तीनों देशों की पोत-निर्माण क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी पहली SSN (परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बी) का विकास शामिल है।
  - **स्तंभ 2:** यह स्वायत्त प्रणालियों, AI, विद्युतचुंबकीय युद्ध, मॉडलिंग और सिमुलेशन जैसे आठ उन्नत सैन्य क्षमता क्षेत्रकों के संयुक्त विकास पर केंद्रित है।

UTKARSH CIVIL SERVICES

शांगरी-ला डायलॉग

(स्रोत: INDIAN EXPRESS)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग में ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए वियतनाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।

मुख्य बिन्दु:

- ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो "दागो और भूल जाओ" के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी गति मैक 2.8 है, यह स्टील्थ क्षमता से युक्त है और इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है।

शांगरी-ला डायलॉग

- इसे एशिया के प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे प्रतिवर्ष सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- यह सुरक्षा संबंधी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए रक्षा क्षेत्र के वैश्विक नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाता है।
- यह रणनीतिक विमर्श, द्विपक्षीय वार्ता और रक्षा सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)

(स्रोत: THE HINDU)

चर्चा में क्यों?

- भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 1 जून, 2026 को लागू हुआ।

मुख्य बिन्दु:

CEPA क्या है?

- एक CEPA पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से कहीं आगे जाता है । जहाँ पारंपरिक एफटीए केवल वस्तुओं पर केंद्रित होते हैं, वहीं सीईपीए दो अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक प्रतिबद्धताओं से जोड़ता है, जिसमें वस्तुओं में तरजीही व्यापार, सेवाओं का उदारीकरण, निवेश संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति और सरकारी खरीद शामिल हैं।

भारत-ओमान CEPA की प्रमुख विशेषताएँ

- **भारतीय निर्यात के लिए व्यापक बाजार पहुँच:** भारत के 99.38% निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुंच, जबकि MFN व्यवस्था के तहत यह केवल 15.33% थी।
- ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अपने उन्नत बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से व्यापक GCC बाजार के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 11.18 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 10.61 अरब डॉलर था।
- **सेवाओं का सशक्त उदारीकरण :** ओमान ने 127 सेवा उप-क्षेत्र खोले हैं, जो किसी भी GCC देश द्वारा भारत को दिया गया अब तक का सबसे व्यापक प्रस्ताव है। ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए 100% प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।
- **व्यापार सुगमीकरण उपाय:** ओमान भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को स्वीकार करेगा। इससे परीक्षण में होने वाली देरी कम होगी और निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत में कमी आएगी।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन

(स्रोत: INDIAN EXPRESS)

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य और उसके आसपास अवैध रेत खनन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों की आलोचना की है।

मुख्य बिन्दु:

अवैध रेत खनन

- **विधिक स्थिति:** 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957' के तहत रेत (सैंड) को 'लघु खनिज' माना गया है।

- **परिभाषा:** 'खनिज रियायत नियम, 2016' के अनुसार, बिना आवश्यक अनुमति के सर्वेक्षण, अन्वेषण और खनन करना अवैध खनन है।
- MMDR अधिनियम के तहत, बिना वैध लाइसेंस या पट्टे या समेकित लाइसेंस के खनिजों का खनन या परिवहन करना, या धारा 23C के तहत राज्य सरकारों द्वारा लागू नियमों का उल्लंघन करना अवैध खनन के अंतर्गत आता है।
- **दुष्प्रभाव:**
  - o पर्यावरण को नुकसान
  - o जैव विविधता कम
  - o खनन माफियाओं के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या
  - o राजस्व की हानि जैसी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

अवैध रेत खनन रोकने के लिए सुरक्षा उपाय

- **दिशानिर्देश:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 'सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश (2016)' और 'प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश (2020)' जारी किए गए हैं।
- **तकनीक की सहायता से निगरानी:** 'खनन निगरानी प्रणाली (MSS)' के जरिए सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों के माध्यम से निगरानी की जाती है।
- **खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017:** इसमें खनिज खनन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है।
- **जुर्माना और दंड:** 'MMDR संशोधन अधिनियम, 2015' के तहत भारी जुर्माने, 5 वर्ष तक कारावास की सजा तथा मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन जैसे प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य

- यह 1979 में अधिसूचित एक संरक्षित क्षेत्र है।
- **अवस्थिति:** यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिलन बिंदु के पास चंबल नदी में स्थित है।
- **प्राप्त अन्य प्रजातियां:** यहाँ रेड-क्राउन रूफ्ड कछुआ, गंगा डॉल्फिन जैसे जीव पाए जाते हैं।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस)

- **प्राप्ति क्षेत्र:** यह प्रजाति भारत में गंगा की सहायक नदियों—चंबल और गिरवा में, और नेपाल में राप्ती-नारायणी नदी में पाई जाती हैं।

संरक्षण स्थिति:

- **IUCN लाल सूची:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972:** अनुसूची I और IV में सूचीबद्ध,
- **CITES:** परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।

UTKARSH CIVIL SERVICES

बन्नी घास के मैदान

(स्रोत: THE HINDU)

मुख्य बिन्दु:

- गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सौर परियोजना को लेकर स्थानीय समुदायों, जैव विविधता और आर्द्रभूमि पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं।
- कच्छ में स्थित बन्नी घास के मैदान एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदानों में से हैं और फकीरानी जाट जैसे पशुपालक समुदायों का समर्थन करते हैं ।
- पास ही स्थित छारी ढांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभयारण्य एक रामसर स्थल है जो प्रवासी पक्षियों और स्थानीय जैव विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213